राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19232/2023

गुनगुन पुत्री पारस मल, आयु लगभग 19 वर्ष, (जन्म तिथि 01.01.2004), जाति - मेघवाल (एससी), निवासी सुभाष कॉलोनी, वार्ड संख्या 09, पीपर सिटी, जोधपुर - 342601 (राजस्थान) ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, जिला जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जिला पाली, पाली (राजस्थान)।

4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ), ब्लॉक सोजत, सोजत, जिला पाली (राजस्थान)।

5. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देवली हुल्ला, ग्राम देवली हुल्ला, ब्लॉक सोजत, सोजत, जिला पाली (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री मनीष व्यास

श्री रजक खान

श्री अजय कुमार ऑगस्टीन

श्री राहुल चौधरी

प्रतिवादी के लिए: श्री हेमन्त चौधरी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

1. याचिकाकर्ता की शिकायत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवली हल्ला, सोजत, जिला पाली के प्रधानाचार्य द्वारा जारी दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक 1) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार उसे अपने पिता की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया था।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता का जन्म 01.01.2004 को श्री पारस मल और श्रीमती विद्या देवी, याचिकाकर्ता के पिता और माता से विवाहेतर संबंध से हुआ था। श्रीमती विद्या देवी का 25.02.2006 को निधन हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता के पिता ने श्रीमती कैलाश देवी से पुनर्विवाह किया, जो पहले से ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देवली हल्ला, ब्लॉक-सोजत, पाली में वरिष्ठ शिक्षिका (विज्ञान) के रूप में सरकार में सेवारत थीं। याचिकाकर्ता के पिता का भी राज्य के लिए सेवा करते हुए 09.05.2022 को निधन हो गया।

2.1. याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई अलग रहने लगे और याचिकाकर्ता को न तो गोद लिया गया, न ही उसकी देखभाल की गई और न ही उसकी सौतेली माँ ने उसका भरण-पोषण किया। चूंकि याचिकाकर्ता पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर थी और उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी सौतेली माँ ने उसकी उपेक्षा की, इसलिए

उसने संबंधित नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। हालाँकि, उसका आवेदन दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक 1) के उपर्युक्त आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया, जिसके कारण तत्काल याचिका दायर की गई।

3. दिनांक 04.01.2024 को नोटिस जारी करते समय, मेरे द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

> याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए 01.09.2022 (अनुबंध-1) के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने का स्पष्ट आधार यह है कि चूंकि उसकी सौतेली मां पहले से ही सरकारी सेवा में है, इसलिए वह राज्य नीति के अनुसार किसी भी लाभ की मांग करने की हकदार नहीं है।
>
> न्यायालय के प्रश्न पर, विद्वान वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता वास्तव में एक अनाथ है क्योंकि उसकी मां का निधन उसके पिता से पहले वर्ष 2016 में हो गया था और 09.05.2022 को सेवा में रहते हुए अपने पिता की मृत्यु होने तक उसकी देखभाल उसके पिता द्वारा नाबालिग के रूप में की जा रही थी, जब वह मात्र 18 वर्ष की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसकी सौतेली मां ने कभी भी याचिकाकर्ता को गोद नहीं लिया और वह अपना स्वतंत्र जीवन जी रही है और याचिकाकर्ता का भरण-पोषण नहीं कर रही है।
>
> इसके बावजूद, लागू राज्य नीति के अनुसार उदारता दिखाने के बजाय, अनाथ याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

नोटिस जारी करें, 20.02.2024 को वापस किया जाना है। नामित वकील के माध्यम से सेवा करने की स्वतंत्रता दी गई है।

दस्ती भी।"

4. प्रतिवादियों द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया है, जिसमें बचाव पक्ष ने कहा है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति की उदार नीति का लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ सरकारी कार्यालय में काम कर रही है, जैसा कि याचिकाकर्ता के मामले में अनुलग्नक-1 से पता चलता है।

5. प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने।

6. याचिकाकर्ता की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अर्थात् उसकी सौतेली माँ का उसके प्रति कोई कानूनी दायित्व नहीं है और किसी भी मामले में, सौतेली माँ की सरकारी नौकरी उसे इस शर्त के साथ नहीं दी गई थी कि वह अपने पिता के निधन के बाद याचिकाकर्ता का भरण-पोषण करे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता न तो अपनी सौतेली माँ की देखभाल में है और न ही उसके साथ रह रही है। यह स्पष्ट है कि सौतेली माँ याचिकाकर्ता के पिता (उसके पति) के निधन के बाद जीवन में आगे बढ़ गई है।

7. उपरोक्त अजीबोगरीब स्थिति को देखते हुए, अनाथ याचिकाकर्ता ने अपने जीवनयापन के लिए आजीविका की तलाश में इस न्यायालय का रुख किया है। इसलिए यह जरूरी है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे सहायता प्रदान करने के लिए लागू अनुकंपा नीतियों का लाभ दिया जाए। नीति का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले की मृत्यु पर जीवनयापन का मार्ग प्रदान करना है, ताकि उसे वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े और वह गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर न हो। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि

मृतक सरकारी कर्मचारी के बदले में सेवा प्रदान करके आश्रित को चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

8. परिणामस्वरूप, याचिका को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

9. प्रतिवादियों को अनुकंपा नीति के अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उसकी पात्रता के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब कॉपी के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने पर दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।